

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 661
8/02/2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

हिंद महासागर में अनुसंधान हेतु पोत के निर्माण में चुनौतियां

661. डा. सांतुन सेन :

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को हिन्द महासागर में अनुसंधान हेतु पोत के निर्माण हेतु निविदाएं प्राप्त करने और जल-तापीय भंडारों के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए किसी जलयान का उपयोग किए जाने में किन्हीं कठिनाइयों अथवा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या इन कठिनाइयों अथवा चुनौतियों ने मंत्रालय द्वारा हिन्द महासागर में शुरू किए गए अनुसंधान अथवा अन्वेषण कार्यक्रमों के उद्देश्यों अथवा परिणामों को प्रभावित किया है अथवा उनमें समझौता करना पड़ा है; और
- (घ) क्या सरकार ने ऐसी कठिनाइयों या चुनौतियों पर काबू पाने या उनका समाधान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं या उपाय किए हैं ?

उत्तर
पृथ्वी विज्ञान मंत्री
(श्री किरन रीजीजू)

- (क) – (घ) मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, गोवा ने हाल ही में एक राष्ट्रीय खुली निविदा प्रक्रिया पूरी की है तथा नए अनुसंधान पोत के निर्माण और वितरण के लिए एक उपयुक्त शिपयार्ड की पहचान की गई है। इसी तरह, हाइड्रोथर्मल निक्षेपों के सर्वेक्षण और खोज के लिए स्वायत्त अंडरवाटर वाहन (AUV) के साथ एक जलपोत किराए पर लेने के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो गई है।

मंत्रालय छह अनुसंधान जहाजों के बेड़े का रख-रखाव करता है, जिनका उपयोग खुले समुद्र और तटीय क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए नियमित रूप से किया जाता है।
